

जन्मदिन की पार्टी में
रईसजादों ने रेस्टोरेंट में
लहराया असलहा,
तड़तड़ाई गोलियां

(आधुनिक समाचार नेटर्वर्क)
 प्रयागराज। घटना 13 मार्च की रात की है। जिस रेस्टोरेंट में यह घटना हुई वह जीएचएस चौराहे के पास स्थित है। यहां जश्न मनाने के लिए एक दर्जन की संख्या में युवक जुटे थे। रात 9:30 बजे के बाद केक काटा जा रहा था। इसी दौरान यहां एक के बाद एक दो

थे। रात 9:30 बजे के बाद केक काटा जा रहा था। इसी दौरान यहाँ एक के बाद एक दो फायर किए गए। सरेआम गोलियाँ चलने से आसपास सनसनी फैल गई। घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें युवक केक काटते दिख रहे हैं और तभी पीछे से गोलियाँ चलने की आवाज सुनाई देती हैं।

फर्जी नंबर प्लेट लगाकर कोयले का परिवहन करने में दो गिरफ्तार

(आधुनिक समाचार नेटवर्क)

अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में शुक्रवार को थाना रोबर्ट्सांज पुलिस को मुख्यीर द्वारा सूचना दी गयी कि एक ट्रेलर नं० एनएल 01 जी 0761 का फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर कोयला लाद कर ले जा रहा है। इस सूचना पर थाना रावर्ट्सगंज

सिंह निवासी चटका थाना सिंगराली जनपद सिंगराली (मध्य प्रदेश) के देख रेख में चलवाया जा रहा था। उक्त ट्रैलर व उस पर लड़े कोयले की अनुमानित कीमत करीब 45 लाख रुपये है। अब उक्त अभियोग की विवेचना धारा 420, 467, 468, 471 भादवि व 4/21 खान खनिज

**स्कूलों में स्वास्थ्य-स्वच्छता और
कल्याण संबंधी जागरूकता जरूरी’**
(अधिकारी सम्मेलन दोर्दोह)
प्रशिक्षण किए गए। सर्वानुमति दी गई है। अधिक किए गए। उन्हें

(आधुनिक समाचार नेटवर्क)
तोपदा। तोपदा आयाष्टां १०

प्रांशक्षण दिया गया। कायेशाला
के सामान अवसर पर सीमाओं

रूप में नामित किया जाएगा। उन्हें स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देने पर और रोगों की रोकथाम के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। हेत्य एंड वेलनेस एंबेसडर हर सप्ताह एक विशेष घटना में विशेष रोचक गतिविधियों के माध्यम से सभी लोगों को सत्र आयोजित करेंगे। प्रत्येक विशेष घटना कक्षा से दो नामित छात्र इन स्वास्थ्य संवर्धन संदेशों को समाज



कीमत 45 लाख) सीज़। एडिशनल एसपी मुख्यालय कालू सिंह ने कहा कि आवेदक कमलेश केवट पुत्र देवनाथ केवट नि 0 ग्राम नौबतपुर थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली द्वारा थाना रावर्टसंगंज पर सूचना दी गयी कि उसके बाह्य संख्या एनएल 01 जी 0761 का फर्जी नम्बर ह्येट लगा कर एक अन्य बाह्य चंलाया जा रहा है, जिसके आधार पर थाना रावर्टसंगंज पर मु0303सं0 190/2024 धारा 419, 420, 465, 468, 471 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना 30नि0 अजय कुमार श्रीवास्तव के द्वारा सम्पादित की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र, डॉ० यशवीर सिंह के निर्देशन में जनपद में अवैध कोयला परिवहन पर रोक लगाने व इसमें संलिप्त अभियुक्तों की

पुलिस द्वारा तथाकथित वाहन
जिसका चेनों ० 407224350863
को हिन्दुआरी पुलिया के पास पकड़ा
गया, जिसका चालक अरुण कुमार
पुत्र राम विशाले पाल निवासी बरगत
थाना बरगवां जिला सिंगरौली मध्य
प्रदेश उम्र करीब 32 वर्ष तथा
सहचालक घनश्याम पुत्र राम अवधि
निवासी भर्भीच थाना चोपन जिला
सोनभद्र उम्र करीब 29 वर्ष का
परिवहन करते हुए पाया गया, जिस
छानबीन के दौरान तथा वारी मुकदम
के द्वारा तस्दीक किये जाने पर
पूर्णतया: कूटरचित दस्तावेज एवं
फर्जी नं ०० पुष्ट पाये जाने पर समझ
करीब 23.00 बजे थाना रावर्टसंगत
पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तगण
उपरोक्त ड्रेलर के साथ गिरफ्ता
किया गया। उल्खनीय है कि चालक
एवं सहचालक दोनों सगे रिस्तेदार
(बहनोंव र साले) हैं, जिनके द्वारा
पूछताछ के दौरान बताया गया विव

अधिनियम के अन्तर्गत होगी।
जिसमे गिरफ्तारी हुए अभियुक्त
व वाहन 1- वाहन संख्या ००१३
०७६१ ट्रेलर के चालक अरुण
कुमार पुत्र राम विशाले पाल निवासी
बरगवा थाना बरगवा जिला
सिंगराली मध्य प्रदेश उप्र करीब
३२ वर्ष। २- वाहन संख्या ००१३
०७६१ ट्रेलर का सहचालक
घनश्याम पुत्र राम अवध निवासी
भर्भईच थाना चोपन जिला सोनभद्रा
उप्र करीब २९ वर्ष। बरामदगी का
विवरण- एक अदद ट्रेलर संख्या
००१३०७६१ मय कोयला
(अनुमानित कीमत ४५ लाख रुपये)
बरामद । गिरफ्तारी/बरामदगी
करने वाली पुलिस टीम का
विवरण- १. ३०८०० अजय कुमार
श्रीवास्तव थाना रॉबटर्सगंज,
जनपद सोनभद्रा । २. है०का०
अनीश कुमार थाना रॉबटर्सगंज

करने के उद्देश्य से मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में 11 से 14 मार्च तक एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डा. सुनील कुमार शर्मा ने कहा- स्कूलों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जागरूकता होना जरूरी है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत आप सभी इस संदेश को पूरी ईमानदारी के साथ शिक्षकों व विद्याधिक्यों तक पहुंचाएं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की प्रशिक्षण के दौरान मिली जानकारियां विद्याधिक्यों से साझा करेंगे। कार्यशाला में स्वास्थ्य व शिक्षा

पोषण की सकारात्मक भूमिका जरुरी है। इसी के मद्देनजर आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल हैल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम शुरू किया गया है। कार्यक्रम के तहत विद्यालयों के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग द्वारा अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किये जाएंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूल जाने वाले बच्चों-किशोरों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जागरूकता पैदा करना तथा विद्यालय स्तर पर संचालित स्वास्थ्य गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्रत्येक विद्यालय से दो शिक्षकों एक महिला व एक पुरुष तक पहुंचाने के लिए हेल्थ वेलनेस मैसेंजर के रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने बताया- इस प्रशिक्षण में मुख्य रूप से किशोर स्वास्थ्य पोषण, मादक द्रव्यों के दुरुपयोग, एचआईवी, इंटरनेट के उपयोग आदि 11 विषयों पर प्रशिक्षण के साथ चर्चा की गई। उन्होंने बताया- स्वास्थ्य विभाग के आठ और शिक्षा विभाग के चार प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। आरबीएसके के नोडल अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. ललित कुमार, डा. अलताफ, डा. केके शर्मा, डा. अशोक और डीईआईसी की प्रबन्धक रचना वर्मा, ने मुख्य

ଆଧୁନିକ ପ୍ରକାଶ

- वाटर प्रूफ शेड
 - पार्किंग की सुविधा
 - मन्दिर की सुविधा
 - सी.सी.टीवी.
 - छोटे-बड़े कार्यक्रमों के अलग-अलग रेट
 - 45000 sq. feet. एरिया
 - हरे-भरे वातावरण
 - AC कमरा (VIP)

CALL: 9519313894.9415608783. 9415608710

आधुनिक समाचार पब्लिशिंग हाउस, यूपीएसआईडीसी, रेमण्ड रोड, और्धोगिक थाने के पीछे भारत पेट्रोलियम के पहले, और्धोगिक क्षेत्र, नैनी, प्रयागराज



सम्पादकीय

‘नया सचिन है, इंतजार करिए चमकते भविष्य का
गत विजेता भारत ने मंगलवार कर दिया लेकिन फिर देखा तो

(छह फरवरी) को सेमीफाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को दो विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही उसने लगातार दूसरी बार फाइनल में अपनी जगह बनाई है। हो सकता है कि आपने अंडर 19 विश्वकप के ज्यादातर मैच नहीं देखे हों। मैंने भी नहीं देखे थे। हाँ अमर उजाला में पढ़कर यह जरूर पता चलता रहा कि भारत अपने मैच लगातार जीत रहा है। क्रिकेटर सरफराज के छोटे भाई मशीर खान के कारण भी सोशल मीडिया पर थोड़ी चर्चा मिल रही थी। इसीलिए सोचा कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल मैच जरूर देखा जाए। इत्तेफाक देखिए कि टीवी के सॉफ्टवेयर में कुछ कमी आने के कारण दक्षिण अफ्रीका की पहले खेली गई पारी नहीं देख पाया। इसके बाद तय किया कि मोबाइल पर टीवी चलाकर या ऑनलाइन स्कोरिंग वेबसाइटों के सहारे मैच को देखा जाएगा। भारत की पारी शुरू होने वाली थी और देखा कि दक्षिण अफ्रीका ने 245 का लक्ष्य दिया है। उसी वेबसाइट पर यह भी



क भारत का टाम ता भजूत ह
तो स्कोर छोटा ही रहेगा। पर
यह क्या हुआ, पहली गेंद ही पर
ही भारत का पहला विकेट गिर
गया। फिर मुशीर खान मैच जिता
देंगे लेकिन एक अच्छा चौका मारने
के बाद मुशीर भी चले गए। इसके
बाद बीच-बीच में मैच देखता रहा।
जब 32 पर चौथा विकेट गिरा तो
मानो दिल ही टूट गया। वेबसाइट
को बंद कर दिया, थोड़ी देर बाद
देखा तो स्कोर 90 पर चार विकेट
ही था। दुआ करते हुए फिर बंद

था। वह युवा खिलाड़ी जनका
कपानी में भारत यह खिताब जीत
चुका है। यह बात और है कि
वक्त के साथ मिली शोहरत के
साथ उन्मुक्त उतना बेहतर प्रदर्शन
नहीं कर पाए और अभी अमेरिका
में लोग खेल रहे हैं। दुआ करिए
कि इस बार खेल रही युवा पीढ़ी
हमें यह खिताब तो दिलाए ही और
आगे भी विश्व चैंपियन बनाए।
और हां फाइनल जरूर देखिएगा
और इन खिलाड़ियों के संघर्ष की
कहानियां भी जानिएं।

यही गति बरकरार रहने की संभावना
भारत में जीडीपी की गणना दो
वर्षों से भी ज्यादी है। इसमें
कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आगामी
वर्षों में भी ज्यादी ज्यादी देशी

वरकार से को जाता है। वास्तविक रियल और नॉमिनल। वास्तविक जीड़ीपी की गणना का आधार वर्ष 2011-12 है और इस अवधि के दौरान वस्तुओं एवं सेवाओं की आकालिक कीमत के अनुसार वस्तुया सेवा का मूल्य आंका जाता है, जबकि नॉमिनल जीड़ीपी के तहत वर्तमान मूल्य पर वस्तुएं सेवा का

The image is a composite of two charts. The top chart is a bar chart with several vertical bars of varying heights, representing data points. The bottom chart is a line graph with a single blue line that starts low on the left and trends upwards towards the right, indicating growth or improvement over time. The overall theme is likely related to economic indicators or financial performance.

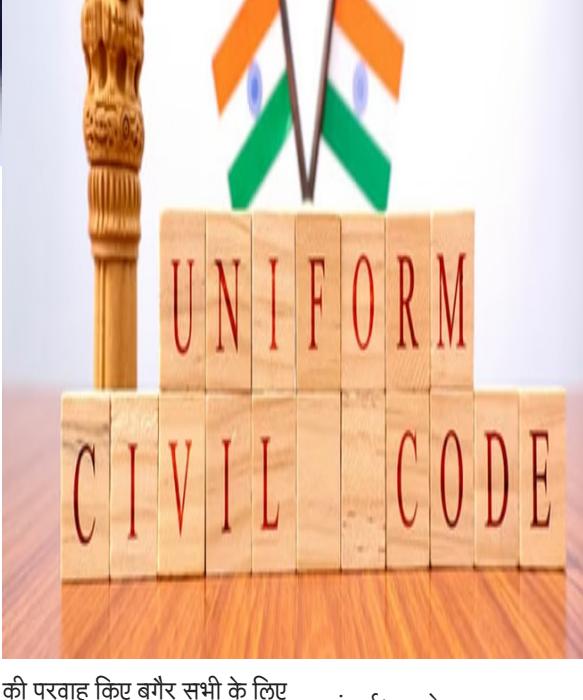
सही दिशा में छोटा कदम पूरे देश के लिए साबित हो सकता है नजीर

उत्तराखण्ड में बन रहा नया कानून संविधान के नजरिये से पूरे देश के लिए नजीर साबित हो सकता है, जिससे प्रेरणा लेकर 'एक देश एक कानून' के तहत यूसीसी को पूरे देश में जल्द लागू करने की जरूरत है। इससे संविधान निर्माताओं द्वारा देखा गया लैंगिक समानता का स्वप्न सही मायने में साकार हो सकेगा। संविधान के प्रावधानों को साकार करते हुए उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर थामी ने समान नागरिक सहित (यूसीसी) पर कानून बनाने की ऐतिहासिक पहल की है। संविधान की शुरुआत 'सत्यमेव जयते' से होती है, जहां सारनाथ का सिंह कानून के शासन के महत्व को दर्शाता है। गणतंत्र के 75 साल बाद भी यूसीसी पर चल रहे असमंजस को संविधान में उकेरे गए पौराणिक आच्यानों से समझा जा सकता है। संविधान सभा में के. एम. मुंशी जैसे सदस्यों की बात मानकर अगर यूसीसी को मूल अधिकार वाले अध्याय में शामिल किया जाता, तो यह कानून सभी के लिए बाध्यकारी हो जाता। मूल में धर्म के आधार पर माहलांड के साथ भेदभाव होना दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉ. राजेंद्र प्रसाद की बात पर अमल करते हुए वर्ष 1956 में हिंदू कोड बिल के साथ मुस्लिम समुदाय के लिए भी कानून बनने चाहिए था। वर्ष 1985 में शाहबान मामले के बाद भी इस बारे में ठोस कदम उठाया जा सकता था। उसके बजाय तुष्टीकरण नीति वे तहत स्प्रीम कोर्ट के फैसले के पलटने से कट्टरपंथी ताक़तों के बढ़ावा ही मिला। इंडोनेशिया, बहरीन, तुकिये और लेबनान जैसे कई मुस्लिम देशों में आधुनिक कानून लागू हैं, तो फिर भारत में ओरैस्टा जैसे कट्टरपंथी नेताओं द्वारा धर्म के आधार पर यूसीसी के विरोध को प्रथानाता कर्यों मिलनी चाहिए। पर्सनल लॉ के नाम पर रजस्वल होने के बाद नाबालिंग मुस्लिम लड़कियों की शादी का समर्थन करने वालों को शरीयत ऐक्ट के धारा 3-बी पढ़ने की जरूरत है। कॉन्स्ट्रैक्ट ऐक्ट की धारा-11 वें तहत ऐसे अनुबंध में दोनों पक्षों का सक्षम यानी बालिंग होने जरूरी है। इसलिए शरीयत ऐक्ट की आड़ में नाबालिंग मुस्लिम बच्चे

लड़कियों का शादी का उम्र 18 से 21 साल करने पर संसद में कई साल से सिर्फ मंथन हो रहा है। उत्तराखण्ड में पूर्व जज की कमेटी ने भी माना है कि बाल-विवाह के पीछे अशिक्षा और गरीबी बढ़ी वजह है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, नाबालिंग बच्चों के सहमति से बने संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। इसलिए लड़कियों की उम्र को बढ़ाने के बजाय लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र को भी 18 साल करने पर विचार होना चाहिए। इससे लैंगिक समानता के साथ कानून-पालन का भाव बढ़ेगा। तीसरा, कुछ लोग यूसीसी को जनसंख्या विस्फोट से निपटने का कारगर उपाय मानते हैं। भारत में कई दशकों से जनसंख्या नियंत्रण पर सिर्फ कानून बनाने की बात हो रही है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि अगले 10 वर्षों में कामकाजी आबादी कम होने के साथ बूढ़ों की तादाद भी बढ़ जाएगी। यूसीसी के तहत लिव-इन से पैदा होने वाले नाजायज बच्चों को भी कानूनी अधिकार मिलेंगे। सरोगेसी के तहत भी लोग के साथ सावधानक अराजकता भी बढ़ सकती है। आईपीसी, सीआरपीसी और एविंडेंस ऐक्ट के औपनिवेशिक कानूनों के बजाय पूरे देश के लिए नए आपराधिक कानून बनाए गए हैं। नकल रोकने के लिए भी संसद से राष्ट्रीय स्तर पर कानून बन रहा है। तीन तलाक पर भी केंद्र सरकार ने प्रभावी कानून बनाया है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत दी गई राज्य की परिभाषा और विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार, संसद से पूरे देश के लिए यूसीसी का कानून बनना चाहिए यूसीसी का मुद्दा 1989 से भाजपा के घोषणा-पत्रों का हिस्सा रहा है। जिस तरीके से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को संसद के कानून से निरस्त किया गया, उसी ठोस तरीके से यूसीसी पर राज्यों के बजाय केंद्रीय स्तर पर अमल की जरूरत है। विधिआयोग की रिपोर्ट में यूसीसी के लागू होने पर अनेक व्यावहारिक अड़चनों का विवरण है। उत्तराखण्ड में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की समिति ने बड़े स्तर पर सभी पक्षों के साथ विरास किया है। उन पहलुओं पर पूरे देश में स्वस्थ

प्रगतिशील समाज के लिए जरूरी पहल, इसमें निहित हैं व्यापक हित

समाज के व्यापक हितों के मद्देनजर समाज के पंथनिरपेक्ष हित चिंतकों को आगे बढ़कर समान नागरिक संहिता की दिशा में पहल करने की जरूरत है, ताकि हम एक प्रगतिशील समाज बन सकें। उत्तराखण्ड सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया है। जानकारी के अनुसार, इसमें सभी नागरिकों के कल्याण के लिए एक जैसे कानून का प्रस्ताव है। हलाल तथा तीन तलाक जैसी अमानवीय प्रथाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सभी धर्मों की तलाकशुदा महिलाओं के लिए समान रूप से भरण-पोषण की व्यवस्था की गई है। सभी लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष कर दी गई है। लिंग-इन संबंधों के कारण अक्सर विवाद और हिंसा की खबरें आती रहती हैं। इससे निपटने के लिए उनका पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। बहुपतने प्रथा को समाप्त करके सभी के लिए केवल एक विवाह का नियम प्रस्तावित है। संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की स्पष्ट व्यवस्था के बाबजूद सरकारें इस दिशा में आगे कदम बढ़ाने से हिचकती रहीं। संविधान का अनुच्छेद 44 सबसे अधिक दुष्प्रचारित हिस्सों में से एक है। इस उपर्युक्त के साथ बहुत अन्याय हुआ है। इसमें देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून बनाने की बात कही गई है। इसमें सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह लिंग, क्षेत्र, भाषा का विवाह-विच्छेद करवें। समानपूर्वक एक-दूसरे से अलग रहने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को भरण-पोषण का अधिकार दिया गया। पिता की संपत्ति में बेटियों को भी अधिकार देने की परंपरा शुरू हुई। संतानों को गोद लेने के मामलों में भी पति के एकाधिकार को तोड़ते हुए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। हिंदू कानून में किए गए सुधारों में मानवाधिकारों और समानता के सिद्धांतों की तरजीह दी गई। परंपरा वोट बैंक खिसकने की स्वार्थी सोच के कारण दूसरी जगहों पर ऐसा नहीं हो सका और उन्हें बेहतरी के मौके से लगातार विचित रखा गया। आधुनिक सोच का लाभ दूसरे मतावलबियों को भी हासिल हो, इसके लिए अदालतें लगातार कोशिश करती रही हैं। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो मामले (1985) में सुनीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह खेद का विषय है कि अनुच्छेद 44 में तय राज्य की जिम्मेदारी अब निर्जीव शब्द समूहों का संग्रह बनकर रह गई है। अदालत ने कहा कि मुस्लिम समाज को इस मामले में पहल करने की जरूरत है, ताकि प्रगति की दौड़ में वे दूसरों से पीछे न रहें। हैरानी की बात यह है कि शाहबानो के जिस मुकदमे में सुनीम कोर्ट ने लोगों से आगे बढ़ने की पहल का आढ़ान किया, उसके दुष्प्रचार ने समान नागरिक कानून की पहल को सबसे मर्मांतक चाट



द ग्रेट राशयन राबरा, जिसन बदल दिया दुनिया के अनाज कारोबार का रिवाज

1803 से उपर की विवरणों में इतिहास में कहीं किसी भी बड़ी तेजी का जिक्र नहीं है। बीसवीं सदी के सातवें दशक की शुरुआत तक महंगाई में गेहूं का योगदान नगण्य था, पर 1970 के दशक में अचानक पूरी दुनिया में अफरा-तफरी मच गई। आइए टाइम मशीन तैयार

जनाज का करना से जूँझ रहा था लिजी कॉलिंघम अपनी मूल्यवान किताब 'द टेस्ट ऑफ वार वर्ल्ड वार दूँ एंड बैटल फॉर फूड' में लिखती है कि दूसरी बड़ी जंतर के दौरान अमेरिका में सेना वे लिए से हतमंद लोग मिलने मुश्किल थे। प्रत्येक पांच में द

बदल दिया था। विसाना की मूल्य समर्थन और स्बिस्टी दी गई थी, जिसका फायदा भरपूर फसलों के तौर पर पककर सामने आने लगा था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद नई तकनीकों से खेती के उत्पादन में और वेची आर्ट करता था। वह सादे बहुतायत अनाज कंपनियों के जरिये किए जाते थे। 70 के दशक की शुरुआत में डॉलर कमज़ोर हो रहा था। गोल्ड स्टैंडर्ड समाप्त हो गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन बुरी तरह परेशान थे। अपेक्षिका का तिर्यक गया।

A yellow backhoe loader is shown working in a field of dry, golden-brown crops. The machine is angled towards the right, with its front loader bucket raised and positioned over the ground. A large cloud of dust is visible behind the machine, indicating active soil disturbance. In the background, there are rolling hills under a clear blue sky.

लगे। यूं तो यह दौर चरम शीत
युद्ध था, मगर अमेरिका और रूस
के बीच कारोबारी रिश्तों की गर्मी

न सपाव्य न्यायालय न समाज नागरिक कानून के नहीं होने के दोषों को उजागर करते हुए इसका तुरंत क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया। वैवाहिक मामलों में वैयक्तिक विधि के दुर्घटनाएँ से विचलित होकर अदालत ने कहा कि अब तो इसका दुर्घटनाएँ कानून को धोखा देने के लिए होने लगा है। जब वैवाहिक साथी से छुटकारा पाना हो, तो कुछ समय के लिए अपना धर्म बदलकर दूसरी शादी कर ली, क्योंकि दूसरे धर्म से जुड़े कानून में उसे मान्यता दी गई है। उसके बाद अपनी मर्जी से तलाक देकर उस महिला से छुटकारा पा लिया, क्योंकि उस धर्म का कानून इसकी इजाजत देता है। सुप्रीम कोर्ट और कई विद्वानों ने इसी कमी की ओर बार-बार इशारा किया, पर हमारे राजनीतिक नेतृत्व के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। प्रो. ताहिर महमूद ने अपनी पुस्तक मुस्लिम पर्सनल लॉ (1977) में तथा न्यायमूर्ति एमएच बेग ने

इम्प्रेसिव कॉर्ट द्वारा अप्रैल 1973 में भी संविधान के अनुच्छेद 44 को अमली जामा पहनाने का आह्वान किया, किंतु शाहबानो प्रकरण के दुःख्खपन से अब भी कोई उबरने को तैयार नहीं है। समाज के व्यापक हितों के मद्देनजर समाज के पंथनिरपेक्ष हित चिंतकों को आगे बढ़कर इस दिशा में पहल करने की जरूरत है। ताकि हम एक

